(1) सतही जल प्रवाह सिंचाई योजनायें अर्थात् भंडारण, टैंक, मोड, योजनायें तथा चेक बांध आदि ।

(2) नदियों तथा नालों पर सतही जल उठाव सिंचाई योजनाये ।

(3) गैर सरकारी कुएं, नलकप तथा पम्पसैट्स ।

(4) कुओं की बोरिंग करना और उन्हें गहरा करना ।

(5) सार्वजनिक नलकूप ।

विवरण

राज्यवार आधार पर कुल सिंचित क्षेत्र (अनन्तिम)

(हजार हैक्टार)

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल सिंचित क्षेत्र 1973–74
1.	आंध्र प्रदेश .	4154
2.	असम (क) .	572
3.	बिहार . .	2797
4.	गुजरात . .	1549*
5.	हरियाणा .	2564
6.	हिमाचल प्रदेश .	156
7.	जम्मू और कश्मीर .	362
8.	कर्नाटक . .	1422
9.	केरल .	636
10.	मध्य प्रदेश .	1733
11.	महाराष्ट्र . .	768
12.	मणिपुर . .	75
13.	मेघालय . .	51(ख)
14.	नागालैंड .	33
15.	उड़िसा . .	1188
16.	पंजाब . .	4619
17.	राजस्थान .	2679
18.	सिक्कम .	उ०न०
19.	तमिलनाडु .	3674
20.	त्रिपुरा .	30
21.	उत्तर प्रदेश .	8492
22.	पश्चिम बंगाल (ग)	1541
23.	संघ क्षेत्र .	136
	अखिल भारत .	40249
	अखिल भारत	40249

(क) इसका सम्बन्ध सन् 1953–54 से है

(ख) इसका सम्बन्ध सन् 1972–73 से है

(ग) इसका संबंध सन् 1967–68 से है

(*) इसका संबंध सन् 1971–72 से है

उ० न० –उपलब्ध नहीं ।

कुल सिंचित क्षेत्र : कुल क्षेत्र जिसकी वर्ष की अवधि में समस्त फसलों के अंतर्गत सिंचाई हुई है । उस सिंचित क्षेत्र को जहां एक से अधिक बार बुवाई हुई है उसे प्रत्येक फसल के लिए अलग क्षेत्र माना गया है ।

दिल्ली अध्यापक परिषद् की मांग

60. श्री कल्याण जन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली अध्यापक परिषद् ने यह मांग की है कि आपातकाल के दौरान अध्यापकों के सेवा रिकार्ड में लिखे गए प्रतिकूल टिप्पण निकाल दिये जायें और कतिपय अध्यापकों को दी गई अनुचित पदोन्नति के मामलों का पुनरीक्षण किया जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : जी, हां। ये मामले विचाराधीन हैं।

आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का सहयोग

61. **श्री कल्याण जैन** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार के सामने कौन सी योजना विचाराधीन है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर) : राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे 1969–70 से चालू किया हुआ है, विश्वविद्यालय और कालेज के छात्रों को सामाजिक सेवा और विकासात्मक कार्यकलापों में लगाने की व्यवस्था पहले से ही करती हैं। 1976–77 से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकलापों को ग्रामीण पुनर्गठन के लिये कार्यक्रमों के आस-पास केन्द्रीत किया गया है। इस योजना को धीरे धीरे व्यापक रुप दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में खोले गये योजना मंच छात्र समुदाय में देश के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता की ओर जागरूकता पैदा करते हैं और योजना बनाने के आरंभिक स्तर से ही उनको राष्ट्रीय विकास के काम में लगाते हैं।

झालावाड़ (राजस्थान) में मध्यम सिंचाई योजनाएं

62. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झालावाड़ जिला (राजस्थान) मे, जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई योजनाएं इस बीच पूरी हो गई हैं और उन पर अब तक कितना धन खर्च हो चुका है और उन पर कुल कितना धन खर्च होगा और उन से कितना लाभ प्राप्त होगा ; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस जिले में कोई नई बृहत् अथवा प्रथम सिंचाई योजना आरम्भ की है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) (क) 7,000 हैक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई के लिए 5.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली भीमसागर स्कीम और प्रति वर्ष 8,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचित करने के लिए 2.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली हरिश्चन्द्र सागर स्कीम से राजस्थान के झालावाड़ जिले को लाभ पहुंचेगा। मार्च, 1977 तक इन स्कीमों पर क्रमशः 62 लाख रूपये और 64 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उस ने झालावाड़ जिले में निम्नलिखित तीन नई मध्यम परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण-कार्य हाथ मे लिए हैं और अन्वेषण कार्य जारी हैं :—

1. मनोहर थाना परियोजना।
2. छापी परियोजना ।
3. गंगारिन परियोजना ।